

गेहूं निर्यात नए रिकार्ड की ओर

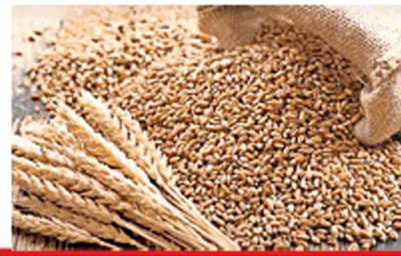
रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले ही इस वर्ष जनवरी तक चार गुना बढ़ चुका था निर्यात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक कर्मांडीटी मार्केट में भारी तेजी का रुख है, जिससे कृषि उत्पादों की निर्यात मांग में तेज इजाफा हुआ है। इस वर्ष जनवरी तक ही भारतीय गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले चार गुना तक बढ़ चुका था, जिसकी मांग फरवरी के आखिरी सप्ताह में युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार बढ़ रही है। मोटे अनाज का निर्यात भी 66 प्रतिशत अधिक हो चुका है। प्रसंस्कृत (प्रोसेस्ड) कृषि उत्पादों की निर्यात मांग भी काफी बढ़ी है। कृषि क्षेत्र को जिसों के निर्यात से नई ऊर्जा मिली है। चालू सीजन में चीनी निर्यात नई ऊंचाई छूने लगा है। युद्ध शुरू होने के बाद कई देशों से गेहूं की मांग आने लगी है। चालू सीजन में 66 लाख टन गेहूं निर्यात हो चुका है, इसके 70 लाख टन की सीमा को पार कर जाने की संभावना है।

जिसों के निर्यात में चावल से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती रही

अवसर

- युद्ध के बाद वैश्विक बाजार में कृषि जिसों की निर्यात मांग और बढ़ी
- जिस निर्यात में अब तक हो चुकी 23 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी



मोटे अनाज की निर्यात मांग में भी इजाफा

मोटे अनाज की निर्यात मांग में भी इजाफा हुआ है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी के दौरान पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 66 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में प्रोसेस्ड फूड में मांस, डेयरी, और पोल्ट्री उत्पादों में 13 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, बागवानी उत्पादों में फल और सब्जियों के निर्यात में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। रूस-यूक्रेन युद्ध से बदली परिस्थितियों में इन सभी उत्पादों की मांग में तेज उछाल दिखने की उम्मीद है।

है जो इस बार और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों की निर्भरता घट सकती है। चालू रबी सीजन में सरसों की फसल बाजार में उतरने लगी है, जिसका खुले बाजार में मूल्य घोषित एमएसपी के मुकाबले बहुत अधिक बोला जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 10 महीने (अप्रैल,

2021-जनवरी, 2022) के दौरान कुल 19.71 हजार करोड़ डालर के जिसों का निर्यात किया गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 15.97 हजार करोड़ डालर मूल्य का निर्यात किया गया था। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्राइवेट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एथारिटी (एपीडा) ने

23.71 हजार करोड़ डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है।

एपीडा के चेयरमैन डा. एम. अंगमुथु ने कहा कि हमारी कृषि निर्यात नीति-2018 का सकारात्मक परिणाम मिलने लगा है। निर्यात के ब्रुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर पूरा जोर है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नगालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम व मेघालय ने निर्यात के राज्य विशिष्ट कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। बाकी राज्यों में भी इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

चावल का निर्यात हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छा रहा है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक इसमें पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि इस सीजन में चीनी का निर्यात 75 लाख टन हो सकता है।